



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

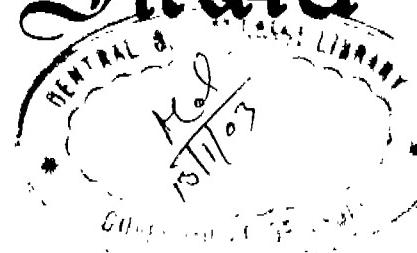
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]
No. 289]नई दिल्ली, मंगलवार, जून 25, 2002/आषाढ़ 4, 1924
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 2002/ASADHA 4, 1924

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2002

सं. 36/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

स.का.पि. 448(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निदेश देती है कि उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं में से प्रत्येक को, व्यापारिश्वति, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे संशोधन के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तस्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रेति में संशोधित या और संशोधित किया जाएगा, अर्थात् :—

सारणी

क्रम. सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
1	2	3
1.	126/94-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2, सितम्बर, 1994	<p>पैरा 6 और उसके स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—</p> <p>“6क. इस अधिसूचना के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रावधान ढाले विना, जहाँ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उस यूनिट को, जिसे संबद्ध राज्य विजली बोर्ड द्वारा इस निमित अनुज्ञात किया गया है, विकास आयुक्त द्वारा अपने डीजल जेनरेटिंग सेटों या कैपटिव विद्युत संयंत्र में उत्पादित अभिशेष विजली का घेरलू टैरिफ क्षेत्र (घ.टै.क्ष.) को विक्रय करने या अन्य शत प्रतिशत नियांतोन्मुख उपकरण को या नियांत प्रसंस्करण जौन या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क या विशेष आर्थिक जौन में यूनिटों को, ऐसी शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट की जाए, अंतरण करने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया है, वहाँ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त ऐसी यूनिट को निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात कर सकेगा—</p> <p>(i) भारत सरकार के व्याणिज्य और उद्योग मंत्रालय के व्याणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 14/1/2001-ईपीजेड, तारीख 7 अगस्त, 2001 द्वारा नियुक्त किए गए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंड के आधार पर घेरलू टैरिफ क्षेत्र में इस प्रकार विक्रय की गई विजली की प्रत्येक यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कञ्ची सामग्री पर उद्घासीय शुल्क के यदि</p>

		<p>उस पर शुल्क से छूट न होती तो, तुल्य रकम के संदाय पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ऐसी अधिशेष बिजली का विक्रय करने के लिए ;</p> <p>(ii) ऐसी अधिशेष बिजली का अन्य शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या निर्यात प्रसंस्करण जोन या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या विशेष आर्थिक जोन को शुल्क के संदाय के बिना अंतरण करने के लिए :</p> <p>परन्तु यह कि प्रदायकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों यूनिटें निर्यात की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उक्त अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंडों के आधार पर मात्रात्मक रूप से इस प्रकार अंतरित प्रत्येक विद्युत यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कच्ची सामग्री की मात्रा के लिए लेखा रखेगी ।”।</p>
2.	1/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 4 जनवरी, 1995.	<p>पैरा 8 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—</p> <p>“9. इस अधिसूचना के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उस यूनिट को, जिसे संबद्ध राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुज्ञात किया गया है, विकास आयुक्त द्वारा अपने डीजल जेनरेटिंग सेटों या कैपिटिव विद्युत संयंत्र में उत्पादित अधिशेष बिजली का घरेलू टैरिफ क्षेत्र (घ.टै.क्ष.) को विक्रय करने या अन्य शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम को या निर्यात प्रसंस्करण जोन या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क या विशेष आर्थिक जोन में यूनिटों को, ऐसी शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अंतरण करने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया है, वहाँ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त ऐसी यूनिट को निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात कर सकेगा—</p> <p>(i) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं0 14/1/2001-ईपीजेड, तारीख 7 अगस्त, 2001 द्वारा नियुक्त किए गए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंड के आधार पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इस प्रकार विक्रय की गई बिजली की प्रत्येक यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कच्ची सामग्री पर उद्ग्रहणीय शुल्क के, यदि उस पर शुल्क से छूट न होती तो, तुल्य रकम के संदाय पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ऐसी अधिशेष बिजली का विक्रय करने के लिए ;</p> <p>(ii) ऐसी अधिशेष बिजली का अन्य शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या निर्यात प्रसंस्करण जोन या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या विशेष आर्थिक जोन को शुल्क के संदाय के बिना अंतरण करने के लिए :</p> <p>परन्तु यह कि प्रदायकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों यूनिटें निर्यात की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उक्त अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंडों के आधार पर मात्रात्मक रूप से इस प्रकार अंतरित प्रत्येक विद्युत यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई</p>

		खपत योग्य और कच्ची सामग्री की मात्रा के लिए लेखा रखेगी ।”।
3.	52/2000-केन्द्रीय उत्पाद शुल्कक, तारीख 19 अक्टूबर 2000.	<p>पैरा 6 के पश्चात् और उसके नीचे प्रथम स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—</p> <p>“7. इस अधिसूचना के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उस यूनिट को, जिसे संबद्ध राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुज्ञात किया गया है, विकास आयुक्त द्वारा अपने डीजल जेनरेटिंग सेटों या कैपटिव विद्युत संयंत्र में उत्पादित अधिशेष बिजली का घरेलू टैरिफ क्षेत्र (घ.टै.क्ष.) को विक्रय करने या अन्य शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम को या निर्यात प्रसंस्करण जोन या साप्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर पार्क या विशेष आर्थिक जोन में यूनिटों को, ऐसी शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अंतरण करने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया है, वहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त ऐसी यूनिट को निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात कर सकेगा—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रीलय के वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं0 14/1/2001-ईपीजेड, तारीख 7 अगस्त, 2001 द्वारा नियुक्त किए गए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंड के आधार पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इस प्रकार विक्रय की गई बिजली की प्रत्येक यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कच्ची सामग्री पर उद्ग्रहणीय शुल्क के, यदि उस पर शुल्क से छूट न होती तो, तुल्य रकम के संदाय पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ऐसी अधिशेष बिजली का विक्रय करने के लिए ; (ii) ऐसी अधिशेष बिजली का अन्य शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या निर्यात प्रसंस्करण जोन या साप्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या विशेष आर्थिक जोन को शुल्क के संदाय के बिना अंतरण करने के लिए : <p>परन्तु यह कि प्रदायकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों यूनिटें निर्यात की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उक्त अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंडों के आधार पर मात्रात्मक रूप से इस प्रकार अंतरित प्रत्येक विद्युत यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कच्ची सामग्री की मात्रा के लिए लेखा रखेगी ।”।</p>
		खपत योग्य और कच्ची सामग्री की मात्रा के लिए लेखा रखेगी ।”।
3.	52/2000-केन्द्रीय उत्पाद शुल्कक, तारीख 19 अक्टूबर 2000.	<p>पैरा 6 के पश्चात् और उसके नीचे प्रथम स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—</p> <p>“7. इस अधिसूचना के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उस यूनिट को, जिसे संबद्ध राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुज्ञात किया गया है, विकास आयुक्त द्वारा अपने डीजल जेनरेटिंग सेटों या कैपटिव विद्युत संयंत्र में उत्पादित अधिशेष बिजली का घरेलू टैरिफ क्षेत्र (घ.टै.क्ष.) को विक्रय करने या अन्य शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम को या निर्यात प्रसंस्करण जोन या साप्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर पार्क या विशेष आर्थिक जोन में यूनिटों को, ऐसी शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अंतरण करने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया है, वहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त ऐसी यूनिट को निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात कर सकेगा—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रीलय के वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं0 14/1/2001-ईपीजेड, तारीख 7 अगस्त, 2001 द्वारा नियुक्त किए गए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंड के आधार पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इस प्रकार विक्रय की गई बिजली की प्रत्येक यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कच्ची सामग्री पर उद्ग्रहणीय शुल्क के, यदि उस पर शुल्क से छूट न होती तो, तुल्य रकम के संदाय पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ऐसी अधिशेष बिजली का विक्रय करने के लिए ; (ii) ऐसी अधिशेष बिजली का अन्य शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या निर्यात प्रसंस्करण जोन या साप्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या विशेष आर्थिक जोन को शुल्क के संदाय के बिना अंतरण करने के लिए : <p>परन्तु यह कि प्रदायकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों यूनिटें निर्यात की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उक्त अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंडों के आधार पर मात्रात्मक रूप से इस प्रकार अंतरित प्रत्येक विद्युत यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कच्ची सामग्री की मात्रा के लिए लेखा रखेगी ।”।</p>

[फा. सं. 305/25/97-एफटीटी]

डॉ. एस. गरबगाल, अवर सचिव

टिप्पणी :

1. मूल अधिसूचना सं. 126/94-के.उ.शु., दिनांक 2 सितम्बर, 1994 सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 2 सितम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार इसका संशोधन अधिसूचना सं. 35/2002-के.उ.शु., दिनांक 24 जून, 2002 [सा.का.नि. 444(अ) दिनांक 24 जून, 2002] के द्वारा किया गया था।
2. मूल अधिसूचना सं. 1/95-के.उ.शु., दिनांक 4 जनवरी, 1995, सा.का.नि. 8(अ), दिनांक 4 जनवरी, 1995, के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार इसका संशोधन अधिसूचना सं. 35/2002-के.उ.शु., दिनांक 24 जून, 2002 [सा.का.नि. 444(अ) दिनांक 24 जून, 2002] के द्वारा किया गया था।
3. मूल अधिसूचना सं. 52/2000-के.उ.शु., दिनांक 19 अक्टूबर 2000, सा.का.नि. 35(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2000 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार इसका संशोधन अधिसूचना सं. 35/2002-के.उ.शु., दिनांक 24 जून, 2002 [सा.का.नि. 444(अ), दिनांक 24 जून, 2002] के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2002

No. 36/2002-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 448(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Notification No. and Date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	126/94- Central Excise, dated the 2 nd September, 1994	After paragraph 6 and the <i>Explanation</i> thereto, the following paragraph shall be inserted, namely:- “ 6A. Without prejudice to other provisions of this notification, where the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise is satisfied that the unit, which has been permitted by the concerned State Electricity Board in this behalf, has been permitted by Development Commissioner to sell into Domestic Tariff Area (DTA) or transfer to other hundred per cent. export oriented undertaking or units in Export Processing Zone or Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone, the surplus power generated in

		<p>its diesel generating sets or captive power plant subject to fulfilment of such conditions as may be specified by the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise on this behalf, the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise may allow the unit -</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) to sell such surplus power in Domestic Tariff Area on payment of an amount equal to the duty leviable on consumables and raw materials but for the exemption of duty thereon, used for generation of each unit of power so sold in the Domestic Tariff Area on the basis of norms approved by the Board of Approvals appointed by the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number 14/1/2001-EPZ dated 7th August, 2001; (ii) to transfer such surplus power to other hundred per cent. export oriented undertaking or unit in Export Processing Zone or Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone without payment of duty: <p>Provided that both supplying and receiving unit shall maintain account for the quantity of consumables and raw materials used in generation of each unit of power so transferred as quantified on the basis of norms approved by the said Board of Approval, for the purpose of calculation of Net Foreign Exchange earning as a Percentage of Export.”</p>
2.	1/95-Central Excise, dated the 4 th January, 1995	<p>After paragraph 8, the following paragraph shall be inserted, namely:-</p> <p>“9. Without prejudice to other provisions of this notification, where the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of</p>

Central Excise is satisfied that the unit, which has been permitted by the concerned State Electricity Board in this behalf, has been permitted by Development Commissioner to sell into Domestic Tariff Area (DTA) or transfer to other hundred per cent. export oriented undertaking or units in Export Processing Zone or Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone, the surplus power generated in its diesel generating sets or captive power plant subject to fulfilment of such conditions as may be specified by the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise on this behalf, the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise may allow the unit -

- (i) to sell such surplus power in Domestic Tariff Area on payment of an amount equal to the duty leivable on consumables and raw materials but for the exemption of duty thereon, used for generation of each unit of power so sold in the Domestic Tariff Area on the basis of norms approved by the said Board;
- (ii) to transfer such surplus power to other hundred per cent. export oriented undertaking or unit in Export Processing Zone or Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone without payment of duty:
Provided that both supplying and receiving unit shall maintain account for the quantity of consumables and raw materials used in generation of each unit of

		<p>power so transferred as quantified on the basis of norms approved by the said Board, for the purpose of calculation of Net Foreign Exchange earning as a Percentage of Export.”.</p> <p>After paragraph 6 and before Explanation below thereto, the following paragraph shall be inserted, namely:-</p> <p>“7. Without prejudice to other provisions of this notification, where the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise is satisfied that the unit, which has been permitted by the concerned State Electricity Board in this behalf, has been permitted by Development Commissioner to sell into Domestic Tariff Area (DTA) or transfer to other hundred per cent. export oriented undertaking or units in Export Processing Zone or Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone, the surplus power generated in its diesel generating sets or captive power plant subject to fulfilment of such conditions as may be specified by the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise on this behalf; the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise may allow the unit-</p> <p>(i) to sell such surplus power in Domestic Tariff Area on payment of an amount equal to the duty leviable on consumables and raw materials but for the exemption of duty thereon, used for generation of each unit of power so sold in the Domestic Tariff Area on the basis of norms approved by the Board of Approvals appointed by the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number 14/1/2001-EPZ dated 7th August, 2001;</p>
3.	52/2000-Central Excise, dated the 19 th October, 2000	

		<p>(ii) to transfer such surplus power to other hundred per cent. export oriented undertaking or unit in Export Processing Zone or Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone without payment of duty:</p> <p>Provided that both supplying and receiving unit shall maintain account for the quantity of consumables and raw materials used in generation of each unit of power so transferred as quantified on the basis of norms approved by the said Board of Approval, for the purpose of calculation of Net Foreign Exchange earning as a Percentage of Export.”</p>
--	--	---

[F. No. 305/25/97-FTT]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

- Note :** 1. The principal notification No. 126/94-Central Excise, dated the 2nd September, 1994 was published in the Gazette of India vide G.S.R. 667(E), dated 2nd Sep, 94 and was last amended by notification number 35/2002-Central Excise, dated the 24th June, 2002[G.S.R. 444(E), dated the 24th June, 2002].
2. The principal notification No. 1/95-Central Excise, dated the 4th January 1995, was published in the Gazette of India vide G.S.R. 8(E), dated 4-1-95, and was last amended by notification number 35/2002-Central Excise, dated the 24th June, 2002[G.S.R. 444(E), dated the 24th June, 2002].
3. The principal notification no. 52/2000 –Central Excise, dated the 19th October, 2000 was published in the Gazette of India vide G.S.R. 803 (E), dated 19th October, 2000 and was last amended by notification number 35/2002-Central Excise, dated the 24th June, 2002 [G.S.R. 444 (E), dated the 24th June, 2002].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2002

सं. 65/2002-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 449(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के विरुद्ध मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं में से प्रत्येक को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधित या और संशोधित किया जाएगा, अर्थात् :—

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	138/91-सीमाशुल्क, तारीख 22 अक्टूबर, 1991	<p>पैरा 3 के पश्चात् और उस पैरा के नीचे पृथम स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—</p> <p>“4. इस अधिसूचना के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उस यूनिट को, जिसे संबद्ध राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुज्ञात किया गया है, विकास आयुक्त द्वारा अपने डीजल जेनरेटिंग सेटों या कैपटिव विद्युत संयंत्र में उत्पादित अधिशेष बिजली का घरेलू टैरिफ क्षेत्र (घ.टै.क्से.) को विक्रय करने या अन्य शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम को या निर्यात प्रसंस्करण जोन या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर पार्क या विशेष आर्थिक जोन में यूनिटों को, ऐसी शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, जो सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, अंतरण करने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया है, वहां सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त ऐसी यूनिट को निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात कर सकेगा—</p> <p>(i) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 14/1/2001-ईपीजे.ड, तारीख 7 अगस्त, 2001 द्वारा नियुक्त किए गए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंड के आधार पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इस प्रकार विक्रय की गई बिजली की प्रत्येक यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कच्ची सामग्री पर उद्ग्रहणीय शुल्क के, यदि उस पर शुल्क से छूट न होती तो, तुल्य रकम के संदाय पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ऐसी अधिशेष बिजली का विक्रय करने के लिए ;</p>

		<p>(ii) ऐसी अधिशेष बिजली का अन्य शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या निर्यात प्रसंस्करण जौन या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या विशेष आर्थिक जौन को शुल्क के संदाय के बिना अंतरण करने के लिए :</p> <p>परन्तु यह कि प्रदायकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों यूनिटें निर्यात की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उक्त अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंडों के आधार पर मात्रात्मक रूप से इस प्रकार अंतरित प्रत्येक विद्युत यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कच्ची सामग्री की मात्रा के लिए लेखा रखेगी ।”।</p>
2.	140/91-सीमाशुल्क, तारीख 22 अक्टूबर 1991	<p>पैरा 2 के पश्चात् और उस पैरा के नीचे स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—</p> <p>“3. इस अधिसूचना के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उस यूनिट को, जिसे संबद्ध राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुज्ञात किया गया है, विकास आयुक्त द्वारा अपने डीजल जेनरेटिंग सेटों या कैपटिव विद्युत संयंत्र में उत्पादित अधिशेष बिजली का घरेलू टैरिफ क्षेत्र (घ.टै.क्स.) को विक्रय करने या अन्य शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम को या निर्यात प्रसंस्करण जौन या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर पार्क या विशेष आर्थिक जौन में यूनिटों को, ऐसी शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, जो सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, अंतरण करने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया है, वहाँ सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त ऐसी यूनिट को निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात कर सकेगा--</p> <p>(i) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं0 14/1/2001-ईपीजे०, तारीख 7 अगस्त, 2001 द्वारा नियुक्त किए गए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंड के आधार पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इस प्रकार विक्रय की गई बिजली की प्रत्येक यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कच्ची सामग्री पर उदग्रहणीय शुल्क के, यदि उस पर शुल्क से छूट न होती तो, तुल्य रकम के संदाय पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ऐसी अधिशेष बिजली का विक्रय करने के लिए ;</p> <p>(ii) ऐसी अधिशेष बिजली का अन्य शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या निर्यात प्रसंस्करण जौन या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या विशेष आर्थिक जौन को शुल्क के संदाय के बिना अंतरण करने के लिए :</p> <p>परन्तु यह कि प्रदायकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों यूनिटें निर्यात की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उक्त अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंडों के आधार पर मात्रात्मक रूप से इस प्रकार अंतरित प्रत्येक विद्युत यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कच्ची सामग्री की मात्रा के लिए लेखा रखेगी ।”।</p>

3.	95/93-सीमाशुल्क, तारीख 2 मार्च, 1993	<p>पैरा 2 के पश्चात् और उस पैरा के नीचे स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—</p> <p>“3. इस अधिसूचना के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उस यूनिट को, जिसे संबद्ध राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुज्ञात किया गया है, विकास आयुक्त द्वारा अपने डीजल जेनरेटिंग सेटों या कैपटिव विद्युत संयंत्र में उत्पादित अधिशेष बिजली का घरेलू टैरिफ क्षेत्र (घ.टै.क्ष.) को विक्रय करने या अन्य शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम को या निर्यात प्रसंस्करण जौन या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी । ॥ या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प ॥ या विशेष आर्थिक जौन में यूनिटों को, ऐसी शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, जो सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अंतरण करने के लिए</p>
4.	96/93-सीमाशुल्क, तारीख 2 मार्च, 1993	<p>पैरा 1 के पश्चात् और उस पैरा के नीचे स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—</p> <p>“2. इस अधिसूचना के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उस यूनिट को, जिसे संबद्ध राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुज्ञात किया गया है, विकास आयुक्त द्वारा अपने डीजल जेनरेटिंग सेटों या कैपटिव विद्युत संयंत्र में उत्पादित अधिशेष बिजली का घरेलू टैरिफ क्षेत्र (घ.टै.क्ष.) को विक्रय करने या अन्य शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम को या निर्यात प्रसंस्करण जौन या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी । ॥ या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प ॥ या विशेष आर्थिक जौन में यूनिटों को, ऐसी शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, जो सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अंतरण करने के लिए</p>

		<p>अनुज्ञात कर दिया गया है, वहां सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त ऐसी यूनिट को निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात कर सकेगा—</p> <p>(i) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं0 14/1/2001-ईपीजेड, तारीख 7 अगस्त, 2001 द्वारा नियुक्त किए गए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंड के आधार पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इस प्रकार विक्रय की गई बिजली की प्रत्येक यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कच्ची सामग्री पर उद्ग्रहणीय शुल्क के, यदि उस पर शुल्क से छूट न होती तो, तुल्य रकम के संदाय पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ऐसी अधिशेष बिजली का विक्रय करने के लिए ;</p> <p>(ii) ऐसी अधिशेष बिजली का अन्य शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख्य उपक्रम या निर्यात प्रसंस्करण जोन या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या विशेष आर्थिक जोन को शुल्क के संदाय के बिना अंतरण करने के लिए :</p> <p>परन्तु यह कि प्रदायकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों यूनिटें निर्यात की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उक्त अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंडों के आधार पर मात्रात्मक रूप से इस प्रकार अंतरित प्रत्येक विद्युत यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कच्ची सामग्री की मात्रा के लिए लेखा रखेगी ।”।</p>
5.	133/94-सीमाशुल्क, तारीख 22 जून, 1994	<p>पैरा 2 के पश्चात् और उस पैरा के नीचे स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित पैरा अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—</p> <p>“4क. इस अधिसूचना के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उस यूनिट को, जिसे संबद्ध राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुज्ञात किया गया है, विकास आयुक्त द्वारा अपने डीजल जेनरेटिंग सेटों या कैपटिव विद्युत संयंत्र में उत्पादित अधिशेष बिजली का घरेलू टैरिफ (घ.टै.क्स.) को विक्रय करने या अन्य शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख्य उपक्रम को या निर्यात प्रसंस्करण जोन या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या विशेष आर्थिक जोन में यूनिटों को, ऐसी शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, जो सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, अंतरण करने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया है, वहां सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त ऐसी यूनिट को निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात कर सकेगा—</p> <p>(i) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं0 14/1/2001-ईपीजेड, तारीख 7 अगस्त, 2001 द्वारा नियुक्त किए गए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंड के आधार पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इस प्रकार विक्रय की गई बिजली की प्रत्येक यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कच्ची सामग्री पर उद्ग्रहणीय शुल्क के, यदि उस पर शुल्क से छूट न होती तो, तुल्य रकम के संदाय पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ऐसी अधिशेष बिजली का विक्रय करने के लिए ;</p> <p>(ii) ऐसी अधिशेष बिजली का अन्य शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख्य उपक्रम या निर्यात</p>

		<p>प्रसंस्करण जोन या साप्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या विशेष आर्थिक जोन को शुल्क के संदाय के बिना अंतरण करने के लिए :</p> <p>परन्तु यह कि प्रदायकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों यूनिटें निर्यात की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उक्त अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदण्डों के आधार पर मात्रात्मक रूप से इस प्रकार अंतरित प्रत्येक विद्युत यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कच्ची सामग्री की मात्रा के लिए लेखा रखेगी ।</p>
6.	53/97-सीमाशुल्क, तारीख 3 जून, 1997.	<p>पैरा 3क के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंसःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—</p> <p>“उक्त अधिसूचना के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उस यूनिट को, जिसे संबद्ध राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुशास्त किया गया है, विकास आयुक्त द्वारा अपने डीजल ऐनरेंटिंग सेटों या कैपेटिव विद्युत संयंत्र में उत्पादित अधिशेष बिजली का घरेलू टैरिफ क्षेत्र (घ.टै.क्ष.) को विक्रय करने या अन्य शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम को या निर्यात प्रसंस्करण जोन या साप्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क या विशेष आर्थिक जोन में यूनिटों को, ऐसी शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, जो सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अंतरण करने के लिए अनुशास्त कर दिया गया है, वहाँ सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त ऐसी यूनिट को निम्नलिखित के लिए अनुशास्त कर सकेगा—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं0 14/1/2001-ईपीजेड, तारीख 7 अगस्त, 2001 द्वारा नियुक्त किए गए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदण्ड के आधार पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इस प्रकार विक्रय की गई बिजली की प्रत्येक यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कच्ची सामग्री पर उद्ग्रहणीय शुल्क के, यदि उस पर शुल्क से छूट न होती तो, तुल्य रकम के संदाय पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ऐसी अधिशेष बिजली का विक्रय करने के लिए ; (ii) ऐसी अधिशेष बिजली का अन्य शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या निर्यात प्रसंस्करण जोन या साप्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या विशेष आर्थिक जोन को शुल्क के संदाय के बिना अंतरण करने के लिए : <p>परन्तु यह कि प्रदायकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों यूनिटें निर्यात की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उक्त अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदण्डों के आधार पर मात्रात्मक रूप से इस प्रकार अंतरित प्रत्येक विद्युत यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कच्ची सामग्री की मात्रा के लिए लेखा रखेगी ।</p>
7.	137/2000- सीमाशुल्क, तारीख 19 अक्टूबर, 2000	<p>उक्त अधिसूचना में,—</p> <p>(क) आरंभिक पैरा में, शर्त (5) के खंड (viii) में “शुल्क के संदाय पर” शब्दों के स्थान पर “भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, साजस्व विभाग की अधिसूचना सं0 80/97-सीमाशुल्क, तारीख 21 अक्टूबर, 1997 में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क के संदाय</p>

	<p>पर ” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;</p> <p>(ख) पैरा 7 के पश्चात् और उस पैरा के नीचे स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—</p> <p>“8. इस अधिसूचना के अन्य उपर्युक्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उस यूनिट को, जिसे सबद्ध राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुज्ञात किया गया है, विकास आयुक्त द्वारा अपने डीजल जेनरेटिंग सेटों या कैपटिव विद्युत संर्यंत्र में उत्पादित अधिशेष बिजली का घरेलू टैरिफ क्षेत्र (घ.टै.क्षे.) को विक्रय करने या अन्य शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम को या निर्यात प्रसंस्करण जोन या साप्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क या विशेष आर्थिक जोन में यूनिटों का, ऐसी शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, जो सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, अंतरण करने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया है, वहाँ सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त ऐसी यूनिट को निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात कर सकेंगा—</p> <p>(i) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं 14/1/2001-ईपीजेड, तारीख 7 अगस्त, 2001 द्वारा नियुक्त किए गए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंड के आधार पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इस प्रकार विक्रय की गई बिजली की प्रत्येक यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कच्ची सामग्री पर उद्ग्रहणीय शुल्क के, यदि उस पर शुल्क से छूट न होती तो, तुल्य रकम के संदाय पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ऐसी अधिशेष बिजली का विक्रय करने के लिए ;</p> <p>(ii) ऐसी अधिशेष बिजली का अन्य शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या निर्यात प्रसंस्करण जोन या साप्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या विशेष आर्थिक जोन को शुल्क के संदाय के बिना अंतरण करने के लिए :</p> <p>परन्तु यह कि प्रदायकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों यूनिटें निर्यात की प्रतिशतता के रूप में शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन करने के प्रयोजन के लिए उक्त अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंडों के आधार पर मात्रात्मक रूप से इस प्रकार अंतरित प्रत्येक विद्युत यूनिट के उत्पादन में प्रयोग की गई खपत योग्य और कच्ची सामग्री की मात्रा के लिए लेखा रखेगी ।”।</p>
--	--

[फा. सं. 305/25/97-एफटीटी]

डी. एस. गरबयाल, अवर सचिव

टिप्पणी :

- मूल अधिसूचना सं. 138/91-सीमाशुल्क, दिनांक 22 अक्टूबर, 1991, सा.का.नि. 639(अ), दिनांक 22 अक्टूबर, 1991, के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार इसका संशोधन अधिसूचना सं. 64/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 24 जून, 2002 [सा.का.नि. 445(अ), दिनांक 24 जून, 2002] के द्वारा किया गया था।
- मूल अधिसूचना सं. 140/91-सीमाशुल्क, दिनांक 22 अक्टूबर, 1991, सा.का.नि. 641(अ), दिनांक 22 अक्टूबर, 1991, के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार इसका संशोधन अधिसूचना सं. 64/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 24 जून, 2002 [सा.का.नि. 445(अ), दिनांक 24 जून, 2002] के द्वारा किया गया था।
- मूल अधिसूचना सं. 95/93-सीमाशुल्क, दिनांक 2 मार्च, 1993, सा.का.नि. 254(अ), दिनांक 2 मार्च, 1993, के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार इसका संशोधन अधिसूचना सं. 64/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 24 जून, 2002 [सा.का.नि. 445(अ), दिनांक 24 जून, 2002] के द्वारा किया गया था।
- मूल अधिसूचना सं. 96/93-सीमाशुल्क, दिनांक 2 मार्च, 1993, सा.का.नि. 255(अ), दिनांक 2 मार्च, 1993, के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार इसका संशोधन अधिसूचना सं. 64/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 24 जून, 2002 [सा.का.नि. 445(अ), दिनांक 24 जून, 2002] के द्वारा किया गया था।

5. मूल अधिसूचना सं. 133/94-सीमाशुल्क, दिनांक 22 जून, 1994, सा.का.नि. 526(अ), दिनांक 22 जून, 1994, के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार इसका संशोधन अधिसूचना सं. 64/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 24 जून, 2002 [सा.का.नि. 445(अ), दिनांक 24 जून, 2002] के द्वारा किया गया था।
6. मूल अधिसूचना सं. 53/97-सीमाशुल्क, दिनांक 3 जून, 1997, सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 3 जून, 1997, के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार इसका संशोधन अधिसूचना सं. 64/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 24 जून, 2002 [सा.का.नि. 445(अ), दिनांक 24 जून, 2002] के द्वारा किया गया था।
7. मूल अधिसूचना सं. 137/2000-सीमाशुल्क, दिनांक 19 अक्टूबर, 2000, सा.का.नि. 804(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2000, के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार इसका संशोधन अधिसूचना सं. 64/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 24 जून, 2002 [सा.का.नि. 445(अ), दिनांक 24 जून, 2002] के द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2002

No. 65/2002-CUSTOMS

G.S.R. 449(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sr. No	Notification No. and Date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	138/91- Customs, dated the 22nd October, 1991.	After paragraph 3 and before first <i>Explanation</i> below that paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely:- “4. Without prejudice to other provisions of this notification, where the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs is satisfied that the unit, which has been permitted by the concerned State Electricity Board in this behalf, has been permitted by Development Commissioner to sell into Domestic

	<p>Tariff Area (DTA) or transfer to other hundred per cent. export oriented undertaking or units in Export Processing Zone or Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone, the surplus power generated in its diesel generating sets or captive power plant subject to fulfilment of such conditions as may be specified by the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs on this behalf, the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs may allow the unit-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) to sell such surplus power in Domestic Tariff Area on payment of an amount equal to the duty leviable on consumables and raw materials but for the exemption of duty thereon, used for generation of each unit of power so sold in the Domestic Tariff Area on the basis of norms approved by the Board of Approvals appointed by the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number 14/1/2001-EPZ dated 7th August, 2001; (ii) to transfer such surplus power to other hundred per cent. export oriented undertaking or unit in Export Processing Zone or Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone without payment of duty: Provided that both supplying and receiving unit shall maintain account for the quantity of consumables and raw materials used in generation of each unit of power so transferred as quantified on the basis of norms approved by the said Board of Approval, for the purpose of calculation of Net Foreign Exchange earning as a Percentage of Export.”.
--	--

2.	140/91- Customs, dated the 22nd October, 1991.	<p>After paragraph 2 and before Explanation below that paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely:-</p> <p>“3. Without prejudice to other provisions of this notification, where the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs is satisfied that the unit, which has been permitted by the concerned State Electricity Board in this behalf, has been permitted by Development Commissioner to sell into Domestic Tariff Area (DTA) or transfer to other hundred per cent. export oriented undertaking or units in Export Processing Zone or Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone, the surplus power generated in its diesel generating sets or captive power plant subject to fulfilment of such conditions as may be specified by the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs on this behalf, the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs may allow the unit-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) to sell such surplus power in Domestic Tariff Area on payment of an amount equal to the duty leviable on consumables and raw materials but for the exemption of duty thereon, used for generation of each unit of power so sold in the Domestic Tariff Area on the basis of norms approved by the Board of Approvals appointed by the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number 14/1/2001-EPZ dated 7th August, 2001; (ii) to transfer such surplus power to other hundred per cent. export oriented undertaking or unit in Export Processing Zone or Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone without payment of duty:
----	---	---

		<p>Provided that both supplying and receiving unit shall maintain account for the quantity of consumables and raw materials used in generation of each unit of power so transferred as quantified on the basis of norms approved by the said Board of Approval, for the purpose of calculation of Net Foreign Exchange earning as a Percentage of Export.”.</p>
3.	95/93- Customs, dated the 2nd March, 1993.	<p>After paragraph 2 and before Explanation below that paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely:-</p> <p>“3. Without prejudice to other provisions of this notification, where the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs is satisfied that the unit, which has been permitted by the concerned State Electricity Board in this behalf, has been permitted by Development Commissioner to sell into Domestic Tariff Area (DTA) or transfer to other hundred per cent. export oriented undertaking or units in Export Processing Zone or Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone, the surplus power generated in its diesel generating sets or captive power plant subject to fulfilment of such conditions as may be specified by the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs on this behalf, the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs may allow the unit-</p> <p>(i) to sell such surplus power in Domestic Tariff Area on payment of an amount equal to the duty leviable on consumables and raw materials but for the exemption of duty thereon, used for generation of each unit of power so sold in the Domestic Tariff Area on the basis of norms approved by the Board of Approvals appointed by the notification of the Government of</p>

		<p>India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number 14/1/2001-EPZ dated 7th August, 2001;</p> <p>(ii) to transfer such surplus power to other hundred per cent. export oriented undertaking or unit in Export Processing Zone or Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone without payment of duty:</p> <p>Provided that both supplying and receiving unit shall maintain account for the quantity of consumables and raw materials used in generation of each unit of power so transferred as quantified on the basis of norms approved by the said Board of Approval, for the purpose of calculation of Net Foreign Exchange earning as a Percentage of Export.”.</p>
4.	96/93- Customs, dated the 2nd March, 1993.	<p>After paragraph 1 and before Explanation below that paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely:-</p> <p>“2. without prejudice to other provisions of this notification, where the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs is satisfied that the unit, which has been permitted by the concerned State Electricity Board in this behalf, has been permitted by Development Commissioner to sell into Domestic Tariff Area (DTA) or transfer to other hundred per cent. export oriented undertaking or units in Export Processing Zone or Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone, the surplus power generated in its diesel generating sets or captive power plant subject to fulfilment of such conditions as may be specified by the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs on this behalf, the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs may allow the unit-</p>

		<p>(i) to sell such surplus power in Domestic Tariff Area on payment of an amount equal to the duty leviable on consumables and raw materials but for the exemption of duty thereon, used for generation of each unit of power so sold in the Domestic Tariff Area on the basis of norms approved by the Board of Approvals appointed by the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number 14/1/2001-EPZ dated 7th August, 2001;</p> <p>(ii) to transfer such surplus power to other hundred per cent. export oriented undertaking or unit in Export Processing Zone or Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone without payment of duty:</p> <p>Provided that both supplying and receiving unit shall maintain account for the quantity of consumables and raw materials used in generation of each unit of power so transferred as quantified on the basis of norms approved by the said Board of Approval, for the purpose of calculation of Net Foreign Exchange earning as a Percentage of Export.”.</p>
5.	133/94-Customs, dated the 22nd June, 1994.	<p>After paragraph 4 and the <i>Explanation</i> thereto, the following paragraph shall be inserted, namely:-</p> <p>“4A. Without prejudice to other provisions of this notification, where the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs is satisfied that the unit, which has been permitted by the concerned State Electricity Board in this behalf, has been permitted by Development Commissioner to sell into Domestic Tariff Area (DTA) or transfer to other hundred per cent. export oriented undertaking or units in Export Processing Zone or</p>

		<p>Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone, the surplus power generated in its diesel generating sets or captive power plant subject to fulfilment of such conditions as may be specified by the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs on this behalf, the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs may allow the unit-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) to sell such surplus power in Domestic Tariff Area on payment of an amount equal to the duty leviable on consumables and raw materials but for the exemption of duty thereon, used for generation of each unit of power so sold in the Domestic Tariff Area on the basis of norms approved by the Board of Approvals appointed by the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number 14/1/2001-EPZ dated 7th August, 2001; (ii) to transfer such surplus power to other hundred per cent. export oriented undertaking or unit in Export Processing Zone or Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone without payment of duty. <p>Provided that both supplying and receiving unit shall maintain account for the quantity of consumables and raw materials used in generation of each unit of power so transferred as quantified on the basis of norms approved by the said Board of Approval, for the purpose of calculation of Net Foreign Exchange earning as a Percentage of Export.”</p>
6.	53/97-	After paragraph 3A, the following paragraph shall be inserted,

	Customs, dated the 3rd June, 1997.	<p>namely:-</p> <p>“3B. Without prejudice to other provisions of this notification, where the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs is satisfied that the unit, which has been permitted by the concerned State Electricity Board in this behalf, has been permitted by Development Commissioner to sell into Domestic Tariff Area (DTA) or transfer to other hundred per cent. export oriented undertaking or units in Export Processing Zone or Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone, the surplus power generated in its diesel generating sets or captive power plant subject to fulfilment of such conditions as may be specified by the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs on this behalf, the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs may allow the unit-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) to sell such surplus power in Domestic Tariff Area on payment of an amount equal to the duty leviable on consumables and raw materials but for the exemption of duty thereon, used for generation of each unit of power so sold in the Domestic Tariff Area on the basis of norms approved by the said Board; (ii) to transfer such surplus power to other hundred per cent. export oriented undertaking or unit in Export Processing Zone or Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone without payment of duty: <p>Provided that both supplying and receiving unit shall maintain account for the quantity of consumables and raw materials used in generation of each unit of power so transferred as quantified on the basis of norms approved by the said Board, for the purpose of calculation of Net Foreign Exchange earning as a Percentage of Export.”</p>
7.	137/2000- Customs, dated the 19 th October, 2000.	<p>In the said notification,-</p> <p>(a) in the opening paragraph, in condition (5), in clause(viii), for the words “on payment of duty”, the words, figures and letters “on payment of duty as specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No.80/97-Customs, dated the 21st October, 1997”, shall be substituted;</p> <p>(b) after paragraph 7 and before <i>Explanation</i> below that paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely: -</p> <p>“8. Without prejudice to other provisions of this notification, where the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs is satisfied that the unit, which has been permitted by the concerned State Electricity Board in this behalf, has been permitted by Development Commissioner to sell into Domestic Tariff Area (DTA) or transfer to other hundred per cent. export oriented undertaking or units in Export Processing Zone or</p>

Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone, the surplus power generated in its diesel generating sets or captive power plant subject to fulfilment of such conditions as may be specified by the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs on this behalf, the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs may allow the unit-

- (i) to sell such surplus power in Domestic Tariff Area on payment of an amount equal to the duty leviable on consumables and raw materials but for the exemption of duty thereon, used for generation of each unit of power so sold in the Domestic Tariff Area on the basis of norms approved by the Board of Approvals appointed by the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number 14/1/2001-EPZ dated 7th August, 2001;
- (ii) to transfer such surplus power to other hundred per cent. export oriented undertaking or unit in Export Processing Zone or Software Technology Park or Electronic Hardware Technology Park or Special Economic Zone without payment of duty:
Provided that both supplying and receiving unit shall maintain account for the quantity of consumables and raw materials used in generation of each unit of power so transferred as quantified on the basis of norms approved by the said Board of Approval, for the purpose of calculation of Net Foreign Exchange earning as a Percentage of Export.”

[F. No. 305/25/97-FTT]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

Note:

1. The principal notification No.138/91-Customs, dated the 22nd October 1991, was published in the Gazette of India vide G.S.R. 639(E), dated the 22nd October 1991, and was last amended by notification No. 64/2002-Customs, dated the 24th June 2002 [G.S.R. 445(E), dated the 24th June, 2002].
2. The principal notification No.140/91-Customs, dated the 22nd October 1991, was published in the Gazette of India vide G.S.R. 641(E), dated the 22nd October 1991, and was last amended by notification No. 64/2002-Customs, dated the 24th June 2002 [G.S.R. 445 (E), dated the 24th June, 2002].
3. The principal notification No.95/93-Customs, dated the 2nd March 1993, was published in the Gazette of India vide G.S.R. 254(E), dated the 2nd March, 1993, and was last amended by notification No. 64/2002-Customs, dated the 24th June 2002 [G.S.R. 445 (E), dated the 24th June, 2002].
4. The principal notification No.96/93-Customs, dated the 2nd March 1993, was published in the Gazette of India vide G.S.R. 255(E), dated the 2nd March 1993, and was last amended by notification No. 64/2002-Customs, dated the 24th June 2002 [G.S.R. 445 (E), dated the 24th June, 2002].
5. The principal notification No.133/94-Customs, dated the 22nd June 1994, was published in the Gazette of India vide G.S.R. 526(E), dated the 22nd June 1994, and was last amended by notification No. 64/2002-Customs, dated the 24th June 2002 [G.S.R. 445 (E), dated the 24th June, 2002].
6. The principal notification No.53/97-Customs, dated the 3rd June, 1997, was published in the Gazette of India vide G.S.R. 302(E), dated the 3rd June 1997, and was last amended by notification No. 64/2002-Customs, dated the 24th June 2002 [G.S.R. 445 (E), dated the 24th June, 2002].
7. The principal notification No. 137/2000-Customs, dated the 19th October 2000, was published in the Gazette of India vide G.S.R. 804(E), dated the 19th October 2000, and was last amended by notification No. 64/2002-Customs, dated the 24th June 2002 [G.S.R.445 (E), dated the 24th June, 2002].